

# बदल रहे हैं गांव

**क**हते हैं- भारत गांवों का देश है यानी इस देश की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन वहां जाकर देखें तो हर आदमी यहाँ कहता मिलेगा कि यहाँ तो 'नरक' है। तब क्या यह मान लिया जाए कि भारत की आत्मा नरक में बसती है? गांवों के नरक बनने के कई पहलू हैं, लेकिन इनमें से खास है- आर्थिक विकास का पहलू। लगभग हर कोई कहता रहता है कि गांव की ओर जाने वाले एक रुपये में से 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं। बाकी रकम चोरी हो जाती है। सूचना के अधिकार ने इस चोरी को रोकने का रास्ता भी दिखाया है। आज देश में हजारों गांवों में लोग अपने विकास और कल्याण के लिए बनी योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, हिमाचल-किताब मांग रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ गांवों में एक साल तक लोगों को सूचना के अधिकार कानून की जानकारी देने और इसके इस्तेमाल में उनकी मदद का एक अभियान चलाया गया। कोशिश यह सम्झने की थी कि अगर सूचना के अधिकार का निरंतर इस्तेमाल किया जाए तो गांव में आने वाले पैसे पर क्या फर्क पड़ता है? इस अभियान के नतीजे बेहद उत्साहजनक निकले।

-पटना के सम्मनचक का रहने वाला कुणाल मोची दिहाड़ी मजदूर है। दिनभर मजदूरी करता है तो शाम को घर का चूल्हा जलता है। घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए कुणाल ने पास के गांव में एक किसान विजय यादव के यहां 62 दिन तक मजदूरी की, लेकिन अब वह अपनी मजदूरी का पैसा मांगने पहुंचा तो विजय यादव ने उसे गाली सुनाते हुए भगा दिया।

कुणाल ने विजय यादव के इन चर्तव के खिलाफ पटना के हरिजन थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन वहां से कोई एक्शन नहीं हुआ। तब कुणाल ने हरिजन थाने में दर्ज रिपोर्ट पर हो रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगने के लिए सूचना अधिकार का आवेदन तैयार किया। सूचना के अधिकार की अर्जी डालते ही जैसे सब कुछ बदल गया। थाने से दरोगा साहब खुद कुणाल के घर आए, पूछताछ के लिए उन्होंने विजय यादव को भी वहीं बुला लिया। पुलिस के कंठे तेवर देख, विजय यादव ने भी अपनी गलती, निराश्रित रूप से मान ली और कुणाल को पूरी मजदूरी 7,000 रुपये का भुगतान कर दिया। साथ ही, 20 रुपये के स्टांप पेपर पर लिख कर दिख कि उसने से वह ऐसी गलती नहीं करेगा।

-तमाम सरकारी दायों के बावजूद चित्रकूट जिले के भरबौल गांव के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सत्र 2006-07 को स्कूल ड्रेस और पुस्तकें दिसम्बर के महीने तक नहीं बांटी गई थीं। उस क्षेत्र में काम कर रहे आरटीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने 18 दिसम्बर, 2006 को गांव वालों के साथ एक बैठक की और उन्हे सूचना के अधिकार के बारे में बतया। जब लोगों को पता चला कि वह सूचना के अधिकार के तहत ये जान सकते हैं कि उनके बच्चों को अब तक ड्रेस क्यों नहीं दी गई, तो उसी समय गांव की 27 अनपढ़ महिलाओं ने अपना आवेदन तैयार करवाया और अगले ही दिन जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जाकर उसे जमा किया। इन्हे सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन का असर 15

दिनों के अंदर दिखा। जनवरी के पहले सप्ताह में न सिर्फ भरबौल गांव के प्राथमिक विद्यालय में, बरन पूरे चित्रकूट जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों में किताबों और ड्रेस का वितरण उपलब्ध कराया। बाद में सूचना दी गई कि जिले में एक करोड़, लाख रुपये की पुस्तकें और एक करोड़ नौ लाख रुपये की स्कूल यूनिकार्ड बांटी गयी हैं।

-बहराइच जिले के नई बस्ती गांव में राशन कार्ड होने के बावजूद लोगों को राशन नहीं मिलता था। तब गांव के 54 लोगों ने मिलकर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन डाल कर पूछा कि क्या उनके गांव के लोगों के लिए सरकार को और से राशन आता है? यदि आता है तो उन्हे राशन क्यों नहीं मिल रहा है? धानुमति इन 54 लोगों में से एक थी, जिन्होंने आवेदन करने के लिए सबसे पहले कदम उठाया। फिर क्या था, आवेदन का असर फौरन सामने आया। कोटेदार जो कभी लोगों से सांघे मुंह बात नहीं करता था, गांव के सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता फिर रहा था और सभी से वादा कर रहा था कि अब गलती नहीं करेगा। बस इस बार माफ़ कर दो। लेकिन गांव वाले झंसे में नहीं आए और अपना आवेदन वापस लेने से साफ़ मना कर दिया। गांव वालों को मनाने के लिए कोटेदार ने गांव में एक टुक सब्जी-पूरी बंटवाने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसका यह रिश्ता भी नहीं ली। फिर सब्वाई निकल कर आई। उसके आधार पर एसडीएम ने कोटेदार को बख़रत कर दिया और गांव की खुली बैठक में नए कोटेदार का चयन किया गया। आज नई बस्ती में सभी को पूरा राशन और मिट्टी का तेल सही समय पर, सही कीमत पर मिलता है। अब धानुमति हर मामले में सूचना के अधिकार की अर्जी डालने को तैयार रहती हैं। उनका कहना है- 'अब ना हरिबो'।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 'शिक्षा गारंटी योजना' के तहत एक्सर विद्यालय- 'विद्या केन्द्र'

स्थापित किए गए। विद्या केन्द्र में 30 बच्चों की शिक्षा और मिड डे मील जादि की व्यवस्था है और यह काम केन्द्र के आचार्य की देखरेख में होता है। इसी तरह मिहिनपुरवा विकास खंड के भवानोपुर, निबादनगर और सुजौली गांवों में भी केन्द्रों की स्थापना की गई। भवानोपुर और निबादनगर केन्द्रों में आचार्य कभी-कभी ही दिखते थे। विद्या केन्द्रों की खस्ता दशा देखते हुए ब्रिडिग बाजार निवासी फरीद अंसारी ने इसी अधिकार के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी से कुछ सवाल किए यानी केन्द्र में नामांकित बच्चों की सूची, अटेंडेंस रजिस्टर की फोटोकॉपी, मिड डे मील का व्यौरा मांगा। मांगी गई सूचनाएं तो नहीं मिलीं लेकिन आचार्य अज्ञानक प्रकट हो गए, केन्द्र में नियमित कक्षाएं लगाने लगीं और बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाने लगा। दूसरी ओर सुजौली में भी 2006 में एक विद्या केन्द्र की स्वीकृति मिली, जिसकी खबर गांव में किसी को नहीं थी। विद्या केन्द्र मात्र कागज़ों तक ही सीमित रहा। 'देहात' संस्था से आरटीआई की जानकारी लेने के बाद आनंद प्रकाश पांडे ने आरटीआई के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस बारे में जांच व तालब किया। नतीजतन, विद्या केन्द्र खुला और इसका लाभ प्रामाणों को मिलने लग्य।

सफलता की कहानी



# Now, Ranchi boasts of own Dutch roses

MANOJ PRASAD

RANCHI, DECEMBER 17

**I**T pays to go Dutch. Ask Rasila Kothari, 52, who took to commercial cultivation of Dutch roses in Chandwe village, near Ranchi in Jharkhand.

While it has been quite some time since tech-backed farming of roses began in the states of Maharashtra, Karnataka, Delhi and West Bengal, it was yet to start in Jharkhand where the every day demand of over 5,000 Dutch rose stems until recently met by cultivators from outside the state.

Rasila, armed with a graduate degree in Botany from Ranchi University, decided it was about time the state boasted of its own Dutch roses.

In 2006, she set up a farm on four acres of land provided to her by her husband, Ajit, to grow Dutch roses and exotic flowers like jarbera and carnation.

The farm was named A.R. Farm, after the husband-wife duo, where four greenhouses were set up.

"In a span of just two years, I raised nearly 60,000 Dutch rose



Dutch roses being grown in greenhouses in Chandwe village near Ranchi.

EXPRESS

plants in the greenhouses, each spread over 3,000 square metres and 6.5 metres high," said Rasila.

She added another 5,000 plants this August, which is set to jack up

the production from the current 1,500 to 2,000 stems to 2,500 stems a day. The cost of one stem ranges between Rs 5 and Rs 10.

The specially designed green-

house ensures a controlled temperature of 12-25°C, wind velocity and humidity—all necessary for healthy growth of the flower.

Unlike ordinary roses, Dutch

roses have long stems of about 10-12 inches, big buds, are semi-bloomed and have a longer vase life.

The plants are raised in rows of beds of earth mixed with compost. "Apart from watering the plants, drips are used to provide nutrients," said Rasila.

Their company, which employs six workers and a technician, made an initial investment of Rs 90 lakh, and has so far sold flowers worth more than Rs 60 lakh.

Since the Centre's National Horticulture Board had provided 20 percent subsidy, Rasila is out of debt now, said Ajit.

However, the couple lament lack of state support for such ventures. "Since floriculture is an employment generation vocation, states like Tripura and Maharashtra provide 50 to 70 percent subsidy in it. But in Jharkhand, where soil and climate are much suitable for flower cultivation, there is no such subsidy. Also, if a wholesale market of flowers was set up somewhere close, the middlemen who slice away a huge sum as traders, could be marginalised," said Ajit.

also formed Annadata Farmers' Club to take up their problems with the government and agriculture experts.

Adjoining villages such as Lodipur, Minapur, Rambhadra, Sindhbari, Hariharpur and Nawada Khurd, too, have taken to seed farming more seriously than earlier.

A few km away from Chakbara, live Bindeshwar Prasad Singh and his son, Amod, who work in close coordination with Krishi Vikas Kendra (KVK) to promote cauliflower seed cultivation.

Singh believes in organic farming and has taught farmers to grow two crops — potato and maize — simultaneously with cauliflower seeds in silty loam soil. The three crops also contribute to each other's nutrition.

Singh (70) owns just 2.5 acres of land that fetches him around 1.5 quintals to 2 quintals of cauliflower seeds. He recently purchased two more acres of land. He, too, has got a silver medal in 2007 from the Indian Vegetable Research Institute at Varanasi for adopting and sharing multi-crop method. Farmers, who have followed his multi-crop method, are reaping rich dividends.

Amod, a first class science

graduate, says, "I am very happy helping my father in the fields and want to take the 'Yellow Revolution' along the length and breadth of Vaishali, Samastipur and Darbhanga."

"My father had a petty earning of Rs 700 per month. He had to sell most of our paternal land to support a family of seven," he added.

After doing his matriculation in 1956, Singh took to farming. When the Green Revolution swept Punjab around 1965, he came to know of high-quality seeds of wheat.

When Sonra-64, a wheat variety, fetched an yield of 69 quintals per acre, the development became the turning point for this agriculture enthusiast. During 1966-67, he accepted a challenge from then agriculture minister S N Singh to replicate "the feat at his 14-acre Langanj (Vaishali) plot". Singh, who stayed in Langanj from 1966 to 1973, was successful in doing so.

The experimentation, unfortunately, wasn't taken any further. "It was only when Rajendra Agriculture Research Institute was set up at the village in 2007, my father was provided the technical know-how," said Amod.

सहारा दिल्ली | शुक्रवार • 11 दिसम्बर • 2009

## कृषि आयोग में किसान भी शामिल किए जाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। गन्ना किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के बजाय लाभकारी मूल्य दिए जाने और कृषि आयोग में उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने की लोकसभा में जोरदार मांग की गई।

आवश्यक वस्तु संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के हुकुम देव

नारायण यादव ने गन्ना किसानों की समस्याओं पर सरकार को अड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार

चीनी मिल लॉबी के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, 'चीनी मिल मालिकों को इसलिए नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे चुनाव में बड़े भर-भरकर रुपया पहुंचाते हैं।' उन्होंने कृषि आयोग में किसानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि सूट-बूट पहने और बालतानकित्त कमरों में बैठे जायू लोग कैसे

जान सकते हैं कि कड़ी धूप, भीषण सर्दी और बरसते मेह में किसान कैसे दिन गुजारता है। इसलिए आयोग में गन्ना किसानों को भी शामिल किया जाए।

सपा के शैलेन्द्र कुमार ने सरकार से गन्ना किसानों की समस्याओं को समझने और उन्हें उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य देने की

मांग की। भाजपा के राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकार से जानना चाह कि गन्ना किसानों के लिए जो लाभकारी उचित मूल्य

घोषित किया गया है, उसमें लागत का आधार क्या है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने विपक्ष के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उसने किसानों के कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सपा की बजाय ने मांग की कि गन्ना किसानों को अधिक मूल्य मिलना चाहिए।

सभी दलों ने किसानों को कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य देने की वकालत की

DELHI

THE HINDU • SATURDAY, DECEMBER 26, 2009

## Plan to connect panchayats with setcom centre

Special Correspondent

**JAIPUR:** The Rajasthan Government is planning to connect the Zila Parishad and panchayat samiti headquarters across the State with the setcom centre established in Jaipur with the support of the Indian Space Research Organisation (ISRO) to provide instant information about natural resources at the grassroots.

The ISRO-sponsored setcom project is preparing the data base of natural resources and assets in the desert State after identifying them in each district and tehsil. The State Natural Resources Information System Management Board reviewed the progress of the project at its third meeting organised here over the week-end.

State Chief Secretary T. Srinivasan, presiding over the meeting, said the setcom studio established in Jaipur would be started shortly and the data base falling within the domain of the Agriculture, Irrigation, Forest, Urban Development and Ground Water Departments updated regularly.

The meeting was informed that ISRO had decided to es-

## To provide instant information about natural resources at the grassroots

establish weather stations at the tehsil level in the State and had spotted the sites for them at 90 tehsil headquarters. Thirty of these stations are proposed to be constructed in association with the Agriculture Department this year. The budget for establishment of setcom centres has been enhanced from Rs.10.5 crore to Rs.13.22 crore, while ISRO has agreed to include telemedicine and education centres in the project.

Mr. Srinivasan said the nodal officers were being appointed in the departments concerned for successful implementation of the project. Additional Chief Secretary (Agriculture) S. Ahmed, Principal Water Resources Secretary Ram Lubhaya, Principal Revenue Secretary Ashok Sampatram, Principal Forest Secretary B. L. Arya and Rajasthan Housing Board chairman Lalit Kothari attended the meeting.

# The Yellow Revolution Men

SANTOSH SINGH

PATNA, DECEMBER 17

**A**ROUND this time of the year, bright yellow flowers carpet the fields in scores of villages in Bihar's Vaishali district. They are not mustard crops waiting to burst into full bloom but cauliflower seeds that have ushered in a revolution of sorts — locals term it 'Yellow Revolution' — in the region.

These seeds — which fetch high prices as they are completely organic — are sold across Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra under an exclusive brand called Vaishali under various names like *satya beej*, green seeds and jawahar seeds.

While over three dozen villages under Hajipur, Mahnar and Lalganj blocks in Vaishali cultivate cauliflower seeds along with other crops, the entire Chakbara village near Hajipur is devoted to cauliflower seed cultivation.

The cumulative earning of around 50 farmers from the sale of seeds last year was about Rs 50 lakh.

Sanjiv Kumar, 30, who likes to be called "a professional cauliflower seed grower", told *The Indian Express*: "We are the 'Yellow Revolution' men of Vaishali. High-

quality seeds, sold for up to Rs 4,000 per kg, are reaching across the country. It is time the central and state governments start giving us subsidies than only token appreciations."

Sanjiv informs that Bindeshwar Prasad Singh of the neighbouring Hariharpur village in Hajipur has pioneered the cultivation of cauliflower seeds in the region. "Thanks to Bindeshwar Prasad Singh that youngsters here have found a means to earn money. Cauliflower seed farming is a big hit."

Sanjiv, who has earned a silver medal for agricultural excellence from the Indian Institute of Vegetable Research, Benares, said that since he did not own enough land, he had started contract farming.

Farmers sow cauliflower plants in July and sell the vegetables — grown in two-thirds of their land — by November-December, leaving one-third of the crop for growing cauliflower seeds. The seed is harvested during February and March. A *katha* (1361 sq ft) yields 7-8 kg of seeds. Chakbara grows the seeds in over 100 acres of land.

Dwarik, another young farmer, said that villagers, some three to four years ago, wanted to switch over to potato and tomato after they lost their cauliflower crops to



Cauliflower seeds are sold for up to Rs 4,000 per kg across the country.

EXPRESS

**Farmers sow** cauliflower plants in July and sell the vegetable — grown in two-thirds of their land — by November-December, leaving one-third of the crop for growing cauliflower seeds. The seed is harvested during February and March. A *katha* (1361 sq ft) yields 7-8 kg of seeds. Chakbara grows the seeds in over 100 acres of land

diseases. "Then, we decided to train ourselves at the Indian Institute of Vegetable Research of the

State Farmers' Commission. There we learnt how to stem the rot from plants," he said. The

farmers use a micro-nutrient called *boran* to weed out black rot. A group of young farmers has

# Rural job plan a carbon-credit spinner?

Aurangzeb Naqshbandi

■ [aurangzebnaqshbandi@hindustantimes.com](mailto:aurangzebnaqshbandi@hindustantimes.com)

**NEW DELHI:** As the world continues to debate climate change in Copenhagen, the rural development ministry is looking to reap some green benefits at home.

It is conducting studies to quantify the value of carbon credits generated through the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) activities so that funds can flow into the rural economy.

The world's largest social security scheme — in terms of people covered and money spent to combat rural poverty — has created "green jobs" such as water harvesting, afforestation, soil conservation and land development.

"About 70 per cent of NREGA works are green jobs. These have helped check rising temperature,



■ **National Rural Employment Guarantee scheme has created about 5 million green jobs in rural India.**

HT FILE PHOTO

depleting water table and deforestation," said a ministry official, who didn't wish to be identified.

Rich countries can make up part of their emissions-cutting targets by funding projects that reduce greenhouse gas output in

developing countries. These projects are awarded carbon credits — each representing a tonne of carbon avoided — that can be bought by firms or governments. Carbon trading was first set up under the Kyoto protocol.

## NREGA & CLIMATE CHANGE

■ Rural development ministry conducting study to quantify value of carbon credits generated through NREGA works

■ About 70 per cent of NREGA works are "green jobs" that have helped check rising temperature, depleting water table and deforestation

■ The ministry is assessing if the works can earn it some extra money through carbon trading

The UPA's flagship job scheme has created about 5 million green jobs so far.

According to official data, even if renewable energy is expanded 40-fold, carbon emissions could rise from 1 billion tonnes per year to 3.9 billion tonnes per year by 2031-32. Under energy projections that assume an even higher rate of coal use, such emissions could rise to 5.5 billion tonnes per year by 2031-32.

The ministry has roped in consultants to find the exact nature and magnitude of the green jobs. They will also determine whether services provided under the scheme could generate revenue through carbon trading.

"Poor are most vulnerable to global warming ... There is an urgent need to study the positive impact of NREGA on climate change," the official said.

Simply put, carbon credits are the currency for buying and selling the right to pollute.

The ministry is trying to assess if the works done under NREGA can help it earn money through carbon trading.